



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 3 जनवरी, 2005/13 पौष, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला  
अधिसूचना

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2004

संख्या एच०पी०इ०आर०सी०/414.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (फ) तथा (ब) के साथ पठित धारा 47 की उप-धारा (1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित,

जो इस बावत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, पर विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला -171002 को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

### प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को, उनके अनुज्ञप्त क्षेत्रों में लागू होंगे।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन विनियमनों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
- (ख) "आवेदक" से परसिर का स्वामी या अधिभोगी, जो विद्युत प्रदाय के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करता है, अभिप्रेत है;
- (ग) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) "उपभोग प्रभार" से Kwh (किलोवाट ऑउअर) (होरा) के हिसाब से विद्युत उर्जा के उपभोग से समुचित टैरिफ रेट के गुणित अभिप्रेत है और इसमें, यहाँ कहीं लागू हो, माँग प्रभार/ नियत प्रभार तथा ग्राहक प्रभार इत्यादि, भी आते हैं;
- (ङ) "अतिरिक्त उच्च विभव (EHT)" से 33000 वोल्ट से अधिक बोल्टता पर विद्युत प्रदाय, अभिप्रेत है;
- (च) "उच्च विभव (HT)" से 650 वोल्ट से अधिक और 33000 बोल्ट पर और उस से अनाधिक बोल्टता पर विद्युत प्रदाय, अभिप्रेत है;
- (छ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अपने प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को किसी भी बोल्टता पर विद्युत प्रदाय करने के लिए वितरण प्रणाली को प्रचालित करने और उसका

रखरखाव करने के लिए प्राधिकृत वितरण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;

- (ज) "न्यून विभव (LT)" से 650 वोल्ट तक की बोल्टता पर विद्युत प्रदाय, अभिप्रेत है;
- (झ) "मास" से कलेंडर मास अभिप्रेत है तथा बिलों के प्रयोजन के लिए दो क्रमवर्ती मीटर रीडिंग में आने वाली लगभग 30 दिन की अवधि भी एक मास समझी जायेगी;
- (ञ) "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई कम्पनी या निगम, निकाय या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या कृत्रिम विधिक व्यक्ति आता है, और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, विभाग, राज्य सरकारी उपक्रम तथा उनके कर्मचारी भी आते हैं;
- (ट) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ; तथा
- (ठ) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु यहाँ परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में नियत किए गए हैं ।

3. **प्रतिभूति की अपेक्षा करने की शक्ति.**— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विनियम 4 में यथाउपबन्धित, प्रत्येक व्यक्ति से, जो धारा 43 के अनुसरण में अपने परिसर को विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करता है, उसे प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा जो ऐसे सभी धन के, जो निम्नलिखित के लिए उसको देय हो जाएं, संदाय के लिए :—

- (क) ऐसे व्यक्ति को प्रदाय की गई विद्युत की बावत हो; या
- (ख) यहां कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर ऐसे व्यक्ति को प्रदाय के लिए उपलब्ध कराया जाना है, वहाँ ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर की बाबत हो ।

(2) यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि ठीक समझे, उस अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, विद्युत का प्रदाय करने से या लाइन या संयंत्र या मीटर उपलब्ध करने से इंकार कर सकेगा ।

4. **प्रदत्त की गई या प्रदत्त की जाने वाली विद्युत के लिए प्रतिभूति निक्षेप.**— (1) न्यून विभव (LT) उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के करार की अवधि के दौरान न्यून

विभव (LT) उपभोक्ता हर समय अनुज्ञप्तिधारी के पास, यहाँ चतुर्मासिक, त्रैमासिक, द्विमासिक अथवा मासिक बिलिंग की व्यवस्था लागू है वहाँ क्रमशः पाँच मास, चार मास, तीन मास तथा दो मास के उपभोग प्रभार के बराबर प्रतिभूति रखेगा ।

(2) उच्च विभव (HT) उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के करार की अवधि के दौरान, उच्च विभव (HT) उपभोक्ता हर समय अनुज्ञप्तिधारी के पास दो मास के उपभोग प्रभार के बराबर प्रतिभूति रखेगा ।

(3) अतिरिक्त उच्च विभव (EHT) उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करार की अवधि के दौरान, अतिरिक्त विभव उपभोक्ता हर समय अनुज्ञप्तिधारी के पास दो मास के उपभोग प्रभार के बराबर प्रतिभूति रखेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति पूर्व भुगतान मीटर के माध्यम से विद्युत लेने को तैयार है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति निक्षेप लेने का अधिकार नहीं होगा :

परन्तु यह कि यहाँ विद्यमान उपभोक्ता, जो पूर्वभुगतान मीटर के माध्यम से विद्युत लेने का विकल्प करता है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उस बकाया राशि को, जो अनुज्ञप्तिधारी को तत्समय देय हो अथवा अनुज्ञप्तिधारी को तत्पश्चात् शीघ्र देय होती है, समायोजित करके उक्त उपभोक्ता को अपने पास रखी हुई प्रतिभूति निक्षेप की राशि लौटायेगा ।

(5) विद्युत प्रदाय करने के समय देय प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप का संदाय विनियम 5 में उल्लिखित सपाट दरों पर होगा ।

(6) प्रतिभूति नकद अथवा अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष देय माँगदेय ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी ।

**5. प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप.—** (1) आवेदक उन्हें प्रदाय की जाने वाली विद्युत के लिए, निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित सपाट दरों पर प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप सदंत करेंगे:—



## सारणी

क्रम	प्रवर्ग स्वरूप संख्या	संयोजित भार/संवेदित मांग के प्रति किलो वाट अथवा उसके भाग की दर पर प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप			
		चर्तुमासिक विलिंग	त्रैमासिक बिलिंग	द्विमासिक बिलिंग	मासिक बिलिंग
1	2	3	4	5	6
1.	जनजातीय, दूरस्थ, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में 20 किलोवाट तक के सभी प्रवर्गों के लिए	375	—	—	—
2.	जनजातीय दूरस्थ, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों तथा प्रपुंज प्रदाय के सिवाय, सभी प्रवर्गों के लिए 20 किलोवाट से अधिक पर	—	—	375	—
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्योगों के सिवाय, सभी प्रवर्गों के लिए 20 किलोवाट तक	—	500	—	—
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्योगों तथा प्रपुंज प्रदाय के सिवाय, सभी प्रवर्गों के लिए 20 किलोवाट से अधिक पर,	—	—	—	250
5.	औद्योगिक प्रदाय के सिवाय, शहरी क्षेत्र/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्रों में 20 किलो वाट तक घरेलू प्रदाय, वाणिज्यिक प्रदाय, गैर/ घरेलू गैर-वाणिज्यिक प्रदाय के लिए	—	—	500	—
	घरेलू प्रदाय के लिये—	—	—	1500	—

1	2	3	4	5	6
	वाणिज्यिक प्रदाय/गैर घरेलू/गैर वाणिज्यिक/जल पम्पिंग प्रदाय हेतु—				
6.	औद्योगिक प्रदाय तथा प्रपुंज प्रदाय के सिवाय शहरी क्षेत्रों/नगर निगम/ नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्रों में 20 किलोवाट से अधिक —				
	घरेलू प्रदाय के लिए —	—	—	—	350
	वाणिज्यिक प्रदाय/गैर घरेलू /गैर वाणिज्यिक/जल पम्पिंग प्रदाय हेतु —	—	—	—	1000
<b>उद्योग</b>					
7.	जनजातीय, दूरस्थ, कठिन एवं दुरगम क्षेत्रों के सिवाय सभी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए विद्युत प्रदाय के लिए 20 किलोवाट तक —	—	—	—	1350
8.	सभी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए (20 किलोवाट से 100 किलोवाट तक)के विद्युत प्रदाय के लिए—	—	—	—	1750
9.	सभी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के लिए विद्युत प्रदाय के लिए — 100 किलोवाट से अधिक विद्युत प्रदाय के लिए —	—	—	—	2150

1	2	3	4	5	6
10.	सभी क्षेत्रों में प्रपुंज विद्युत प्रदाय के लिए	—	—	—	1700
11.	सभी क्षेत्रों में मीटर के माध्यम से अस्थायी विद्युत प्रदाय के लिए	—	—	—	1750
12.	मार्ग प्रकाश हेतु 20 किलोवाट से अधिक के लिए	—	—	—	2000

(2) उन उपभोक्ताओं, जिन्हें अतिरिक्त माँग मन्जूर की गई है, के मामले में अतिरिक्त माँग के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप इस तरह से संगणित किया जाएगा मानो कि यह एक नई सेवा है ।

(3) यदि आवेदक इस विनियम के निबंधनों के अनुसार प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप का संदाय नहीं करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय करने से इन्कार कर सकता है ।

**6. पुनर्विलोकन तथा विद्युत प्रदाय के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान.—** (1) **साधारण पुनर्विलोकन.—** विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट बिलिंग अवधि के अध्यक्षीन रहते हुए, उपभोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप की रकम की अपर्याप्ता अनुज्ञप्तिधारी, साधारणतयः प्रतिवर्ष एक बार (अधिमान्यतः सम्बन्धित वर्ष के टैरिफ के संशोधन के उपरान्त) पूर्वर्ती वर्ष के 12 महीनों की अवधि, अप्रैल से मार्च तक, के औस्त उपभोग के आधार पर, पुनर्विलोकित करेगा ।

(2) **अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप के लिये माँग सूचना,—**

- (क) अनुज्ञप्तिधारी, उप-विनियम (1) के पुनर्विलोकन पर आधारित कमी पूरा करने की माँग करेगा;
- (ख) यहाँ उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप अपेक्षित है वहाँ अनुज्ञप्तिधारी देय राशि का उल्लेख करते हुए समर्थक परिकलन सहित उपभोक्ता को 30 दिन की

अग्रिम माँग सूचना भेजेगा ।

(3) **अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप के विलम्बित भुगतान पर अधिभार,—**

- (क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भेजी गई माँग सूचना की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर, उपभोक्ता अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगा ।
- (ख) यदि भुगतान में विलम्ब होता है, तो उपभोक्ता इस विनियम के उप-विनियम (4) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत काटने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से या ऐसी दरों से जैसी आयोग द्वारा समय-समय नियत की जाएं, साधारण ब्याज संदत्त करेगा ।

(4) **प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान न करने पर विद्युत काटना.—** यहाँ इस विनियम के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की माँग की जाती है और उपभोक्ता भुगतान नहीं करता है, तो उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय, बिना और कोई सूचना के, काटा जा सकेगा ।

7. **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज.—** (1) उप-विनियम (2) के अध्याधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति निक्षेप पर उपभोक्ता को 6 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, परन्तु आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संशोधित ब्याज दर विनिर्दिष्ट कर सकेगा और देय ब्याज की रकम निकटतम रुपये तक पूर्णांकित की जायेगी ।

(2) यदि प्रतिभूति निक्षेप की रकम 100 रुपये से कम होती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम जून को उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय बकाया राशि अथवा उसके तत्पश्चात् उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय होने वाली बकाया राशि में प्रतिवर्ष उपभोक्ता को संदेय होने वाला ब्याज समायोजित किया जाएगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को दिये जाने वाले बिलों में, जो पहली जून के पश्चात् देय हों, उपभोक्ता को प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज राशि का उल्लेख करेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति निक्षेप पर उपभोक्ताओं को प्रोदभूत ब्याज का 1 अलग खाता बनाएगा ।

(6) उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट खाते में प्रतिभूति निक्षेप पर प्रोदभूत ब्याज का 30 दिनों की कालावधि के पश्चात् भी समायोजन में विलम्ब करने पर, अनुज्ञप्तिधारी देय ब्याज पर उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से दुगुनी दर पर शास्तिक ब्याज संदत करेगा । अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में यह शास्तिक ब्याज उपभोक्ताओं को पास थ्रू (pass through) नहीं होगा ।

8. मौसमी उद्योगों हेतु विशेष उपबन्ध.— सभी मौसमी उद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय किए जाने के समय विभिन्न उद्योगिक उपभोक्ता प्रवर्गों के लिए नियत सामान्य दरों से दुगुणा प्रतिभूति निक्षेप देना होगा । यदि उपभोक्ता "बन्द मौसम" के प्रारम्भ होने तक विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करता है, तो अगले मौसम में उसे उद्योग आरम्भ करने के लिए अनुज्ञात करने से पूर्व, उसका प्रतिभूति निक्षेप और दुगुणा हो जायेगा ।

9. प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय.— यहाँ विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किसी विद्युत प्रदाय के करार को खत्म कर दिया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति निक्षेप का, यदि कोई हो, उपभोक्ता द्वारा उसे देय बकाया राशि को समायोजित करने के उपरान्त, इकरार के खत्म करने की तारीख से 10 दिन के भीतर, प्रतिदाय करना होगा :

परन्तु यह कि यदि यथाउपरिनिर्दिष्ट के अनुसार प्रतिप्रदाय करने में एक मास से अधिक विलम्ब हो जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इकरार खत्म करने की तारीख से उक्त निक्षेप पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज देगा ।

### प्रकीर्ण

10. प्रत्ययमाप.— अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं का प्रत्ययमापन करेगा और क्रमवर्ती चार बिल चक्करों में 10,000 रुपये से अधिक के चलत व्यतिक्रमियों की सूची समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेगा तथा नियमित रूप से उसको बेबसाईट पर दिखाएगा ।

11. कठिनाईयाँ दूर करना.— यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग, ऐसा कुछ भी कर सकता है अथवा साधारण या विशेष आदेश

द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी समुचित कार्रवाई, जो अधिनियम से असंगत न हो, करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, जो आयोग को ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

12. **आदेश और कार्य-पद्धति-निदेश जारी करना.**— आयोग इस अधिनियम और इन विनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, समय-समय पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और आनुषांगिक तथा प्रासंगिक मामलों के सम्बन्ध में, आदेश और कार्य-पद्धति निदेश जारी कर सकता है ।

13. **निर्वचन.**— इन विनियमों के सम्बन्ध में उद्भूत सभी विवादक, आयोग द्वारा अवधारित किए जायेंगे तथा उन विवादकों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

आयोग के आदेश द्वारा,

इस्ता /—

सचिव ।

### ***AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT***

## **HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA**

### **NOTIFICATION**

*Shimla-2, the 31st December, 2004*

**No. HPERC/414.**—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (v) and (w) of sub-section (2) of section 181 read with sub-sections (1) and (4) of section 47, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, are hereby published as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days

from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171 002.

## DRAFT REGULATIONS

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall be applicable to all distribution licensees in their respective licensed areas, in the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Definitions.**— In these regulations, unless the context otherwise requires.—

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “applicant” means the owner or occupier of any premises who makes an application to the distribution licensee for supply of electricity;
- (c) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (d) “consumption charges” means the consumption of electrical energy in KWh multiplied by appropriate tariff rates and also includes demand/fixed charges, and customer charges etc., wherever applicable;
- (e) “extra high tension (EHT)” means supply at the voltages above 33000 volts;
- (f) “high tension (HT)” means supply at the voltages of more than 650 volts and upto and inclusive of 33000 volts.

- (g) "licensee" means a distribution licensee authorized to operate and maintain a distribution system and supply electricity at any voltage to consumers in the concerned area of supply;
- (h) "low tension (LT)" means supply at the voltages of 650 volts and below ;
- (i) "month" means the calendar month and the period of about 30 days between the two consecutive meter readings shall also be regarded as a month for the purpose of billing;
- (j) "person" shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person and also includes the Central and the State Government Department, the State Government Undertaking and their employees.
- (k) "State" means the State of Himachal Pradesh ; and
- (l) other words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act.

**3. Power to require security.—** (1) The distribution licensee shall require every person, who requires a supply of electricity to his premises in pursuance of section 43 of the Act, to give security as provided in regulation 4, for the payment of all monies, which may become due to the licensee —

- (a) in respect of the electricity supplied to such person; and /or
- (b) where any electric line or electrical plant or electric meter is to be provided for supplying electricity to such person, in respect of the provision of such line, plant and/or meter.

(2) If such person fails to give such security under sub-regulation (1), the distribution licensee may refuse to give the supply of electricity or to provide the, line or plant or meter for the period during which the failure continues.

**4. Security deposit for the electricity supplied or to be supplied .—** (1) The low tension (LT) consumer shall at all times maintain with the licensee an amount equivalent to consumption charges of five months, four months, three months and two months wherever four-monthly, quarterly, bi-monthly and monthly billing respectively is in vogue as security



during the period the agreement for supply of energy to such low tension (LT) consumers is in force:

(2) The high tension (HT) consumers shall at all times maintain with the licensee an amount equivalent to consumption charges of two months as security during the period the agreement for supply of energy to such high tension (HT) consumers is in force.

(3) The extra high tension (EHT) consumers shall at all times maintain with the licensee an amount equivalent to consumption charges of two months as security during the period the agreement for supply of energy to such extra high tension (EHT) consumers is in force.

(4) If any person is prepared to take the supply through a pre-payment meter, the distribution licensee shall not be entitled to collect the security deposit from such person:

Provided that in the case of existing consumers who opt for the supply through the pre-payment meter, the licensee shall refund the amount of the security deposit of such consumer lying with the licensee by adjustment of the then outstanding dues to the licensee or any amount becoming due to the licensee immediately thereafter.

(5) The initial security deposit payable at the time of releasing the supply shall be at flat rates mentioned in regulation 5.

(6) The amount payable towards security shall be in the form of a cash/demand draft (DD) drawn in favour of the licensee.

**5. Initial security deposit.**—(1) The applicants shall pay initial security deposit towards the electricity to be supplied to them at the flat rates as given in the following table:—

**Table**

S.No.	Type of category	Initial security deposit per KW or fraction thereof of connected load/contract demand			
		4 months billing	3 months billing	2 months billing	monthly billing
1	2	3	4	5	6
1.	Tribal areas, remote, difficult and hard areas all categories upto 20 KW.	375	—	—	—

1	2	3	4	5
2. Tribal areas, remote, difficult and hard areas-all categories above 20 KW except industry and bulk supply	—	—	375	
3. Rural areas all categories upto 20 KW, except industries	—	500	—	
4. Rural areas all categories above 20 KW, except industries and bulk supply	—	—	—	
5. Urban areas/Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayats area-DS- CS, ND/NCS categories up to 20 KW except industries				
DS	—	—	500	
CS/NDNCS/WPS	—	—	1500	
6. Urban areas/ Municipal Corporation/ Municipal Council /Nagar Panchayats-DS, CS, NDNCS categories above 20 KW except industries and bulk supply.	—	—	—	
DS	—	—	—	
CS/NDNCS/WPS	—	—	—	
<b>Industries</b>				
7. Small and medium industries power supply upto 20 KW for all areas except tribal, remote, difficult and hard areas	—	—	—	
8. Small and medium industrial power supply (Above 20 kW to 100 kW) for all areas.	—	—	—	

1	2	3	4	5	6
9. Large industries power supply (above 100 kW) for all areas	—	—	—	2150	
10. Bulk supply (BS) for all areas	—	—	—	1700	
11. Temporary metered supply for all areas	—	—	—	1750	
12. Street lighting above 20 KW	—	—	—	2000	

(2) In the case of consumers who have sanctioned additional demand, the additional security deposit shall be calculated for the additional demand as if it is a new service.

(3) If the applicant does not make payment of initial security deposit in terms of this regulation, the licensee can refuse to release supply.

**6. Review and payment of additional security deposit for the electricity supplied.—** (1) **General review,**— Subject to the billing periods as specified in regulation 4, the adequacy of the amount of security deposit in respect of consumers shall be reviewed by the licensee generally once in every year (preferably after revision of tariff for the respective year) based on the average consumption for the period representing 12 (twelve) months from April to March of the previous year.

**(2) Demand notice for additional security deposit.—**

- (a) Based on review as per sub-regulation (1), demand for shortfall will be made by the licensee :
- (b) Where the consumer is required to pay additional security deposit, the licensee shall issue to the consumer a 30 days' advance demand notice specifying the amount payable with supporting calculations.

**(3) Surcharge for belated payment of additional security deposit.—**

- (a) The consumers shall pay the additional security deposit within thirty days from the date of service of the demand notice issued by the licensee.
- (b) If there is any delay in payment, the consumer shall pay simple interest thereon at 12% per annum or at such rates as may be fixed by the Commission from time to time, without prejudice to the licensee's right to disconnect supply of electricity, as per sub-regulation (4) of this regulation.

**(4) Disconnection for non-payment of security deposit for the electricity supplied.—** Where additional security deposit is demanded by the licensee in terms of this regulation, and the consumer does not make the payment, the supply to the consumer shall be liable for disconnection, without any further notice.

**7. Interest on security deposit payable by the licensee.—** (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the licensee shall pay simple interest on security deposit of a consumer @ 6%, per annum provided that the Commission may specify a revised rate of interest from time to time by notification in the Official Gazette, and amount of interest payable shall be rounded off to the nearest rupee.

(2) Where the security deposit is less the rupees 100, no interest shall be payable thereon.

(3) The interest accruing to the credit of the consumer shall be adjusted annually against the amounts outstanding from the consumer to the licensee as on 1<sup>st</sup> June of every financial year and the amounts becoming due from the consumer to the licensee immediately thereafter.

(4) The licensee shall duly show the amounts becoming due to the consumer towards interest on the security deposit in the bills raised on the consumer and due after 1<sup>st</sup> June.

(5) The distribution licensee shall maintain for accrual of interest on security deposit of the consumers a separate account.

(6) The licensee shall pay penal interest on the interest payable at twice the rate specified under sub-regulation (1) for the delay in making the adjustments for interest on security deposit beyond a period of 30 days in making the adjustments for interest on security deposit in the account referred to in sub-regulation (5). This penal interest shall not be a pass through to the consumers in the licensee's Annual Revenue Requirement.

**8. Special provision for seasonal industries.**— All the seasonal industrial consumers shall be required to deposit the Security at the time of release of connection at double the normal rates for different categories of industrial consumers. In case the consumer fails to clear the energy bill at the time of start of “OFF-SEASON”, the Security Deposit shall further be doubled before he is allowed to run his industry at the time of start of next season.

**9. Refund of security deposit.**— Where an agreement for supply of electricity is terminated as per the terms and conditions of supply, the licensee shall be required to refund the security deposit if any, after making adjustments for the amounts outstanding from the consumer to the licensee, within one month of the effective date of termination of the agreement:

Provided that if such refund is delayed beyond the period of one month as specified above, the licensee shall pay simple interest on such deposit @ 12 % per annum from the effective date of termination of the agreement without prejudice to other rights and remedies of the consumer.

### Miscellaneous

**10. Credit Rating.**— The licensee shall carry out the credit rating of consumers and publish the list of continued defaulters for amount exceeding Rs. 10,000 in the four consecutive billing cycles in the newspapers and host the same on its website on quarterly basis.

**11. Power to remove difficulties.**— In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may do or undertake things, or by general or special order, direct the licensee to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

**12. Issue of orders and practice directions.**— Subject to the provisions of the Act, and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and procedures to be followed for such implementation and matters incidental or ancillary thereto.

**13. Interpretation.**— All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

By Order of the Commission.

Sd/-

Secretary.

